(घ) अब तक कितनी राशि दी गई है और कितनी बाकी है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). सूचना उपलब्ध नहीं है। सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि कर्मचारियों को बकाया रकमों का भुगतान जल्दी ही कर दिया जाय और शीघ्रतापूर्वक भुगतान करने के लिए उसने समय समय पर हिदायतें जारी की हैं। जहां तक सरकार को मालूम है, बकाया रकमें अधिकांश कर्मचारियों को चुकायी जा चुकी हैं। सरकार का ख्याल है कि प्रश्न में मांगी गयी सूचना को भारत भर में फैले विभिन्न कार्यालयों और विदेशों के भारतीय मिशनों से इकट्ठा करने में जो परिश्रम करना पड़ेगा वह निकलने वाले परिणाम को देखते हुए बहुत अधिक होगा।

योजना के अन्तर्गत न आने वाली सरकारी नौकरियों पर प्रतिबन्ध

२४७६. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत न आने वाली सरकारी नौकरियों पर लगा प्रतिबन्ध न्यायसंगत है ;

(ख) यह कब तक चलेगा ; और

(ग) क्या इससे सरकारी कार्यक्षमता की हानि नहीं होती ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाजपेयी) : (क) जी हां, प्रतिबन्ध का उद्देश्य सरकारी प्रशासन-व्यय में कमी करने का है।

(ख) फिलहाल यह ३१-१२-६१ तक चलेगा।

(ग) ऐसे संकेत मिलते हैं कि प्रतिबन्ध से प्रशासनीय क्षेत्रों में उन कर्मचारियों के प्रसार की गति रोक रखी है जिनका योजना की स्कीम तथा सुरक्षा (Scheme and Security) से किसी तरह का सीधा संबंध नहीं है इससे प्रशासनीय कार्य क्षमता को भी कोई हानि नहीं हुई है।

राजस्थान में केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के केन्द्र

२४७७. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सेवाओं के लिये होने वाली परीक्षाओं का केन्द्र राजस्थान में क्यों नहीं रखा जाता ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाजपेयी) : संघ लोक सेवा आयोग (U.P.S.C.) द्वारा दिल्ली से बाहर ली जाने वाली परीक्षाओं के केन्द्र आयोग द्वारा तत्संबंधी कारणों को ध्यान में रखते हुये निश्चित किये जाते हैं। नये केन्द्रों के खोलने में राज्य सरकारों आदि के परामर्श से काफी विस्तृत काम करना होता है, तथा आवश्यकतानुसार स्थिति को बराबर ध्यान में रखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में आयोग ने पांच नये केन्द्र खोलने का निश्चय किया है। राजस्थान में एक केन्द्र खोलने का प्रश्न भी आयोग ने राजस्थान सरकार के साथ हाथ में लिया है, तथा आयोग इस विषय पर सक्रिय विचार कर रहा है।

Requirements of States for Rehabilitation of Flood Victims

2478. **Shri Nagi Reddy:**
Shri Chintamoni Panigrahi:
Shrimati Ila Palchoudhuri:
Shri B. C Mullick:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have asked various State Governments to intimate to the Centre their requirements for rehabilitating the large number of people affected by the recent floods;

(b) if so, the details of the communications received from the State Governments; and

(c) the action taken, thereon?

The Deputy Minister of Home Affairs (Shrimati Alva): (a) The rehabilitation of flood victims is the responsibility of the State Governments. They were, therefore, requested only to state whether any special assistance from Centre was required.

(b) and (c). Only the Governments of Maharashtra, Mysore and Kerala have approached the Centre for financial assistance. The Government of Maharashtra asked for a 'Ways and Means' advance of Rs. 3 crores for relief and rehabilitation of the people affected by the recent floods in Poona. This amount has been sanctioned. The Governments of Mysore and Kerala have asked for financial assistance to the extent of Rs. 3 crores and Rs. 1.80 crores respectively for the victims of floods in their States. The matter is under consideration.

Lecture Tours by Ministers and Deputy Ministers

2479. **Shri A. M. Tariq**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Ministers and Deputy Ministers who went on lecture tour of foreign countries during the year 1960-61 up-to-date;

(b) details of amount paid to them by foreign institutions by way of their fees and other emoluments;

(c) whether this amount was deposited by those Ministers etc. with Government; and

(d) if so, the details of the amount actually deposited by them and the amount retained by them in lieu of travelling and other expenditure incurred?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Pilot Project in Orissa

2480. **Shri Chintamoni Panigrahi**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the pilot project which was proposed to be started in Boipariguda in Orissa in the gramdan villages to be worked by Akhil Bharat Sarva Seva Sangh has been set up by now;

(b) what are the details of schemes of such pilot projects in the gramdan areas; and

(c) how do they differ from development schemes carried in N.E.S. or C.D. areas?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): (a) Yes, sir.

(b) and (c). A list of schemes taken up in Boipariguda pilot project and development schemes carried in N.E.S. or C.D. areas is given below. Some of the important schemes included in the C.D. areas have been taken up in Boipariguda project as well.

I. Details of schemes of pilot project in Boipariguda.

(1) Panchayat.

(2) Credit and Marketing.

(3) Other Co-operative Organisation.

(4) Education.

(5) Agriculture and Animal Husbandry.

(6) Social Amenities.

(7) Special Programme e.g. Workshop, Legal aid, Research, Investigation and evaluation.

II. Details of development schemes carried in N.E.S. or C.D. areas.

(1) Agriculture extension and Animal Husbandry.

(2) Irrigation, Reclamation and Soil Conservation.

(3) Health and Rural Sanitation.

(4) Education.